



DIGITAL ADVANCEMENT OF RURAL POST OFFICE FOR A NEW INDIA

## **Press Brief on DARPAN**

For more than 150 years, the Department of Posts (DoP) has been the backbone of the country's communication and has played a crucial role in the country's socio-economic development. It touches the lives of Indian citizens in many ways: delivering mails, accepting deposits under Small Savings Schemes, providing life insurance cover under Postal Life Insurance (PLI) and Rural Postal Life Insurance (RPLI) and providing retail services like bill collection, sale of forms, etc. The Department of Posts also acts as an agent for Government of India in discharging other services for citizens such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) wage disbursement and old age pension payments. With 1.5 lakh Post Offices (approximately) , the Department of Posts has the most widely distributed postal network in the world.

2. Trends such as urbanisation, increased demand for financial services, increased funding by the government for the weaker sections and the rural sector, have opened up new opportunities for the Department of Posts, which in turn has necessitated development of new processes and supporting technology. The Department of Posts is also faced with twin challenges of increasing competition and continuing advances in communication technology,

especially in mobile telephony and the Internet. In order to provide the best-in-class customer service, deliver new services and improve operational efficiencies, the Department of Posts has undertaken an end to end IT modernization project to equip itself with requisite modern tools and technologies. The IT modernisation project intends to achieve the following:

- I. Wider reach to the Indian populace through more customer interaction channels
- II. Better customer service
- III. Growth through new lines of business
- IV. IT enablement of business processes and support functions

3. As a part of IT modernization project, the Department of Posts (DoP) has carried out business process reengineering across various functional areas and has created To-Be processes that will enable it to achieve these objectives. As an achievement, Department of Posts has established 991 ATMs across the country, which are interoperable with other banks and the common people has directly benefited with the wide network of Department of Posts especially in rural areas. Till now, 1,12,85,217 transactions have been carried out on the DOP's ATMs out of which 70,24,214 transactions have been

done by the non-DOP customers. Department of Posts is the only Government player in this space.

4. The DARPAN – “Digital Advancement of Rural Post Office for A New India” Project is a part of the larger IT modernisation project being undertaken by the Department of Posts with a project outlay of Rs. 1400 Cr (approximately). The goal of the project is to provide a low power technology solution (Information and Communications Technology Device) to each Branch Postmaster (BPM) which will enable each of approximately 1.29 Lakhs Branch Post Offices (BOs) to improve the level of services being offered to rural customers across all the states.

5. The primary business goal of the DARPAN project is to improve the quality of service, add value to services and achieve “financial inclusion” of un-banked rural population, while taking advantage of this opportunity to increase revenue traffic. The Project has the potential to make a significant contribution to these goals. The project shall increase the rural reach of the Department of Posts and enable Branch Offices (rural Post Offices) BOs to increase traffic of all financial remittances, savings accounts, Rural Postal Life Insurance, and Cash Certificates; improve mail operations processes by allowing

for automated booking and delivery of accountable article; increase revenue using retail post business; provide third party applications; and make disbursements for social security schemes such as MGNREGS.

6. As on 15.12.2017, 43171 Branch Post Offices (Rural Post Offices) have been migrated under the “**DARPAN**” project with the aim of financial inclusion of Rural population of the country. It is targeted to complete the project by March’2018.

SOURCE

PROJECT MANAGEMENT UNIT  
DEPARTMENT OF POSTS, NEW DELHI – 110001

No. 12-10/2017-PMU (Pt)

## **दर्पण - प्रेस ब्रीफ**

डाक विभाग, 150 वर्षों से अधिक समय से देश की संचार व्यवस्था का आधार रहा है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह, भारतीय नागरिकों के जीवन से अनेक प्रकार से जुड़ा हुआ है, यथा, डाक वितरण, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशि स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत जीवन बीमा कवर प्रदान करना तथा बिल संग्रहण, फार्मों की बिक्री जैसी रिटेल सेवाएं प्रदान करना आदि। डाक विभाग, नागरिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना (मनरेगा) मजदूरी संवितरण और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसी अन्य सेवाओं के संवितरण में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। डाक विभाग के पास लगभग 1.5 लाख डाकघरों से युक्त नेटवर्क है, जोकि विश्व का सर्वाधिक व्यापक डाक नेटवर्क है।

2. शहरीकरण, वित्तीय सेवाओं की अधिकाधिक मांग, कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा आधिक्य में राशि प्रदान कराए जाने जैसी प्रवृत्तियों ने डाक विभाग के समक्ष कई नई संभावनाएं रखी हैं, जिसके परिणामस्वरूप नई प्रक्रियाओं और सहायक प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। डाक विभाग को संचार प्रौद्योगिकी, विशेषकर मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट के क्षेत्र में निरंतर बढ़ती

प्रतिस्पर्धा और निरंतर होती प्रगति की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने, नई सेवाएं संवितरित करने तथा प्रचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार करने के क्रम में, डाक विभाग ने एंड-टू-एंड आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत की है जो विभाग को अपेक्षित आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से लैस करेगी। आई टी आधुनिकीकरण परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- I. ग्राहकों के साथ संवाद के अधिकाधिक माध्यमों के जरिए आमजन तक व्यापक पहुंच
- II. बेहतर ग्राहक सेवा
- III. नए प्रकार के व्यवसाय के जरिए संवृद्धि
- IV. व्यावसायिक प्रक्रियाओं तथा सहायक प्रकार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाना

3. आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के एक भाग के रूप में, डाक विभाग (डीओपी) ने विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में व्यवसाय की प्रक्रिया को पुनर्व्यवस्थित किया है तथा टू-बी प्रक्रियाओं का सृजन भी किया है, जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसे सक्षम बनाएगा। एक उपलब्धि के रूप में, डाक विभाग ने समूचे देश में 991 एटीएम स्थापित किए हैं, जो दूसरे बैंकों के साथ अंतर्प्रचालन में सक्षम हैं तथा आमजन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क से सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।

अब तक डाक विभाग के एटीएम से 1,12,85,217 लेन-देन किए गए हैं, जिसमें से 7024,214 लेन-देन ऐसे लोगों द्वारा किए गए हैं, जो डाक विभाग के ग्राहक नहीं हैं। इस क्षेत्र में डाक विभाग एकमात्र सरकारी सेवा प्रदाता है।

4. **दर्पण** : “डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया”, यानी नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों की डिजिटल उन्नति, डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही वृहद आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का कुल परिव्यय 1400 करोड़ रुपये (लगभग) है। इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा पोस्टमास्टर को ऊर्जा की कम खपत वाले प्रौद्योगिकी समाधान (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाधान) प्रदान करना है, जिनकी मदद से लगभग 1.29 लाख शाखा डाकघर, सभी राज्यों में ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार ला पाएंगे।

5. दर्पण परियोजना का प्राथमिक व्यावसायिक लक्ष्य, सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रदान की जा रही सेवाओं को और अधिक आकर्षक बनाना और बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्रामीण जन के “वित्तीय समावेशन” के लक्ष्य को प्राप्त करना है और ऐसा करने की प्रक्रिया में इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजस्व अर्जन को बढ़ाना है। यह परियोजना, इन लक्ष्यों को हासिल करने की भरपूर क्षमता रखती है। दर्पण परियोजना, डाक विभाग की



ग्रामीण पहुंच को बढ़ाते हुए शाखा डाकघरों के माध्यम से वित्तीय धन-प्रेषण के साथ-साथ बचत बैंक से संबंधित कार्य, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के विस्तार और नकद-पत्रों की बिक्री में वृद्धि लाएगी। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना, लेखादेय डाक-वस्तुओं की ऑटोमेटेड बुकिंग और संवितरण की व्यवस्था करते हुए, डाक प्रचालन संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार लाने और रिटेल डाक व्यवसाय के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी करने, तृतीय पक्षकारों के एप्लीकेशन उपलब्ध कराने और मनरेगा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु संवितरण की सुविधा प्रदान कराने में भी सक्षम है।

6. 15.12.2017 की स्थिति के अनुसार, देश के ग्रामीण जन के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से, 43,171 शाखा डाकघरों को “दर्पण” परियोजना के अंतर्गत माइग्रेट कर दिया गया है। इस परियोजना को मार्च, 2018 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्रोत

परियोजना प्रबंधन इकाई  
डाक भवन, न्यू दिल्ली - 110001

No. 12-10/2017-PMU (Pt) दिनांक 20.12.2017

## **Frequent Asked Questions & Answers**

### **Q1. What is DARPAN Project?**

**Ans.** The Rural Information Communication Technology (RICT) Project is a part of the larger IT modernisation project, India Post 2012, being undertaken by the Department of Posts. The RICT Project is named as DARPAN - Digital Advancement of Rural Post Office for a New India.

### **Q2. What is the goal of DARPAN Project?**

**Ans.** The goal of DARPAN Project is to provide a low power technology solution (ICT Device) to each Branch Postmaster (BPM) which will enable each of approximately 1.29 lakh Extra Departmental Post Offices (EDOs) to improve the level of services being offered to rural customers.

The primary business goal of the DARPAN Project is to improve the quality of service, add value to services and achieve “financial inclusion” of un-banked rural population, while taking advantage of this opportunity to increase revenue traffic.

### **Q3. What is the vision of DARPAN Project?**

**Ans.** The vision of DARPAN Project is as under:

- a. To increase the rural reach of the Department of Posts and enable EDOs to increase traffic of all financial remittances, savings accounts, Rural Postal Life Insurance, and Cash Certificates;
- b. Improve mail operations processes by allowing for automated booking and delivery of accountable article; increase revenue using retail post business;
- c. Provide third party applications a platform for rural reach;
- d. Make disbursements for social security schemes such as MGNREGS etc.

### **Q4. How far we have reached till now?**

**Ans.** As of now the DARPAN Project have been successfully rolled out in 43171 BO's across the country as on date and offering core banking services (CBS) and Electronic Money Order (eMO) across the length and breadth of the country in would be rolled out in 1.29 lakhs locations.

### **Q5. What are the services offered to the citizens of India by this project?**

**Ans.** Services offered are as under:

- A. **Core Banking Services (CBS):** DARPAN Project CBS Client application of rural BOs is the frontend solution of the Finacle rolled out in the Account offices for Post Office Savings

Bank (POSB) operations of the DOP. As part of DARPAN Project, the CBS client applications have been rolled out in BOs where ever Rural System Integration (RSI) solution have gone live. The DARPAN Project CBS Client application version 1.3.1 is being implemented, which covers the following

1. Cash Deposits in SB and RD
2. Withdrawal from SB
3. New Account Opening for SB/RD/TD
4. Higher value Withdrawal
5. Mini Statement
6. Aadhar Seeding
7. Daily Transaction report

This application is used for the disbursement of social security benefits to the needy across the country such as MGREGS, Old age Pension, DBT etc.

Overall 35626 BOs are doing CBS transactions out of the 40455 BOs roll out till 6-12-17. Other BOs could not do CBS transactions due to various reasons including poor connectivity at the Bos.

**Roll out BOs have done 16.82 million Transaction involving Rs.20 billion average amounts involved per transaction is Rs1189/-**

B. Electronic Money Order (eMO): money order delivery is made easy and quick and the volume is increasing on eMO through devices.

**Q6. How the citizens would be benefitted from this project?**

Ans: Benefits to the citizens:

- a. Provide banking solutions to the un-bank rural population
- b. CBS solutions – deposit and withdraw from anywhere
- c. Ease of deposit and withdrawal and real-time account update
- d. Rural postal life insurance would be available to the citizens in last mile of the country
- e. Other postal services as eMO just in hours (online Bos) in any part of the country
- f. Disbursal of govt. schemes as MNREGS, Old age Pension
- g. Any other government schemes in future
- h. Speed post booking from their next door

**Q7. How can we align this project with the government mission of “Digital India”?**

Ans: *“The vision of Digital India programme is to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy”*

DARPAN Project supports the vision by providing the financial services and citizens benefit schemes as old age pension, MNREGS etc. digitally to the citizens in the last mile of the country through the applications like CBS, Micro ATM, eMO and many more.

**Q.8 What Next?**

Ans : Upcoming services:

	Future Services	Status
1.	Mail Operations, speed post booking and delivery, registered article booking and	Under live testing into the field
2.	Aadhar enabled payment, Deposits, transfers and bill payments	advanced phase and would be available soon
3.	The DOP card based Payment as Micro ATM, Deposits, transfers and bill payment	Would be available soon
4.	Postal Life Insurance – new policy and renewal	Under final stage of testing
5.	Post Bank Application	Under advanced stage of development
6.	Point of Sale – Stamps and other postal article	Under final testing and would be available soon

**Q9. What are the challenges faced during this project and what are the achievements?**

Ans: Different Challenges were in the way of achieving the goal but with the dedicated hard work from a team of Government officials, Industry experts, consultants and technology vendors have overcome these and made a great achievement such as:

	Challenges	Achievement
1.	Connectivity	Major challenges going to the rural part of the country Connectivity was provided by private mobile operators Transaction happening in approx. 80% of the successful rolled out location More than 17 million transactions so far and increasing INR 20 billion by value INR 1189 average per transaction
2.	Training	Department have trainers from its officials Online training setup available at any time Training provided to the BPM in their local languages for better understanding
3.	Awareness	Running multiple drives to spread awareness Handholding support for ease of using the technology Classroom and orientation programmes

		Citizen awareness programmes advertisements
4.	Power Situation	Power situation is not uniform throughout the rural India Solar Solution with UPS have been provided to 75% of the BPM where the power situation is below average Additional battery with separate charging module BPM can work with 2 batteries for 3 days
5.	Speed and Registered Post to the villages	Speed post and registered post can now be booked from the next door Real time tracking can also be provided through RICT devices (in future) Real time tracking is available online Logistics companies have started availing the benefit of India post network and adding revenue

#### SOURCE

PROJECT MANAGEMENT UNIT  
DEPARTMENT OF POSTS, NEW DELHI – 110001

No. 12-10/2017-PMU (Pt) dated 21.12.2017

## प्रश्न एवं उत्तर

### **प्रश्न 1: दपण परियोजना क्या है?**

उत्तर : ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आरआईसीटी) परियोजना, डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही भारतीय डाक 2012 नामक वृहद आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा है। इस आरआईसीटी परियोजना का नाम दपण रखा गया है। दपण का अर्थ है : डिजिटल एडवांस्मंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फोर ए न्यू इंडिया यानी नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नति।

### **प्रश्न 2: दपण परियोजना का लक्ष्य क्या है?**

उत्तर : दपण परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक शाखा पोस्टमास्टर को ऊजा का कम खपत वाले प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है। इसका मदद से लगभग 1.29 लाख अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान का जा रहा सेवाओं में सुधार ला पाएंगे। दपण परियोजना का प्रार्थमिक व्यावसायिक लक्ष्य, सेवा का गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रदान का जा रहा सेवाओं को और अधिक आकर्षक बनाना और बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्रामीण जन के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और ऐसा करने का प्रक्रिया में, इस अवसर का लाभ उाते हुए राजस्व अजन को बढ़ाना है।

### **प्रश्न 3: दपण परियोजना का समग्र उद्देश्य क्या है?**

उत्तर : दपण परियोजना का समग्र उद्देश्य निम्नानुसार है :-

(क) डाक विभाग का ग्रामीण पहुंच को बढ़ाना और अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के माध्यम से वित्तीय धन-प्रेषण के साथ-साथ बचत बैंक खाता से संबंधित कार्य, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के विस्तार और नकद पत्रों का बिक्री में वृद्धि लाना।

(ख) लेखादेय डाक-वस्तुओं का ऑटोमैटिड बुकिंग और संवितरण का व्यवस्था करते हुए डाक प्रचालन संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार लाना और रिटेल डाक व्यवसाय के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी करना।

(ग) तृतीय पक्षकारों के एप्लिकेशनों के लिए ग्रामीण पहुंच वाला मंच प्रदान करना।

(घ) मनरेगा आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु संवितरण का सुविधा प्रदान करना।

#### **प्रश्न 4: अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?**

उत्तर : अद्यतन स्थिति के अनुसार, दपण परियोजना को देशभर के 43171 शाखा डाकघरों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। ये शाखा डाकघर, देश के कोने-कोने में कोर बैंकिंग सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक मनीआडर जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह परियोजना देशभर के 1.29 लाख शाखा डाक घरों में कार्यान्वित की जाएगी।

#### **प्रश्न 5: इस परियोजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं?**

उत्तर : इस परियोजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नानुसार हैं:-

(क) कोर बैंकिंग सेवा : ग्रामीण शाखा डाकघरों हेतु लागू दपण परियोजना सीबीएस क्लाइंट एप्लिकेशन, फिनैकल द्वारा प्रदान किया गया समाधान है। इसका कार्यान्वयन डाक विभाग के डाकघर बचत बैंक प्रचालना हेतु इसके लेखा-कार्यालयों में किया गया है। दपण परियोजना के तहत, सीबीएस क्लाइंट एप्लिकेशन को उन शाखा डाकघरों में लागू किया गया है, जिनमें ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेशन (आरएसआई) समाधान की व्यवस्था है। दपण परियोजना सीबीएस क्लाइंट एप्लिकेशन के वजन 1.3.1 का कार्यान्वयन कार्य जारी है। इसके दायरे में निम्नलिखित कार्य आते हैं:-

1. बचत बैंक तथा आवर्त जमा खातों में नकद जमा
2. बचत खातों में से आहरण
3. बचत बैंक/आवर्त जमा/सर्वाधिक जमा के नए खाते खोलना
4. अधिक राशि का आहरण
5. लघु विवरणी
6. आधार जोड़ना
7. दैनिक लेन-देन का रिपोर्ट

इस एप्लिकेशन का इस्तेमाल देशभर में जरूरतमंद लोगों को मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, प्रत्यक्ष लाभान्तरण आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों का संवितरण करने के लिए किया जा रहा है।

06.12.2017 की स्थिति के अनुसार, जिन 40,455 शाखा डाकघरों में इस एप्लिकेशन का रोल-आउट किया गया है, उनमें से 35,626 शाखा डाकघर सीबीएस लेन-देन का कार्य कर रहे

ह। अन्य शाखा डाकघरों में विभिन्न कारणों, जैसे कि खराब कनेक्टिविटी आदि के कारण सीबीएस लेन-देन नहीं हो पा रहा है।

सीबीएस रोल-आउट वाले शाखा डाकघरों में कुल 16.82 मिलियन लेन-देन काय हुए हैं, जिनका कुल मूल्य 20 बिलियन ₹. है। इनमें से प्रत्येक लेन-देन का औसत मूल्य 1189/- ₹.

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मनीआडर :- इस सेवा के जरिए मनीआडरों के संवितरण का काय आसान और त्वरित हो गया है। विविध उपकरणों की मदद से इलेक्ट्रॉनिक मनीआडरों का मात्रा में वृद्धि हो रहा है।

**प्रश्न 6 नागरिकों को इस परियोजना से किस प्रकार लाभ मिलेगा?**

उत्तर : नागरिकों को मिलने वाले लाभ:-

- (क) उन ग्रामीण लोगों को बैंकिंग समाधान प्रदान करना, जहां बैंक नहीं हैं।
- (ख) सीबीएस समाधान - कहीं भी पैसा जमा करा सकते हैं और निकाल सकते हैं।
- (ग) पैसा जमा कराना और निकालना आसान है और खर्चा के लिए रॉयल - टाइम अपडेट की सुविधा है।
- (घ) देश के अंतिम छोर तक नागरिकों को ग्रामीण डाक जीवन बीमा उपलब्ध होगा।
- (ङ) ईएमओ जैसी अन्य डाक सेवाएं, देश के किसी भी भाग में घंटों में ही (ऑन लाइन बीओएस) उपलब्ध हो जाएंगी।
- (च) मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन जैसी सरकारी स्कीमों का संवितरण
- (छ) किसी अन्य भावी सरकारी योजना का लाभ
- (ज) अपने घर के नजदीक ही स्पीड पोस्ट बैंकिंग की सुविधा

**प्रश्न 7. "डिजिटल इंडिया" मिशन से इस परियोजना को कैसे जोड़ सकते हैं ?**

उत्तर : "डिजिटल इंडिया" प्रोग्राम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और अर्थव्यवस्था को जानकारी से लैस समाज में परिवर्तित करना।



दपण परियोजना सीबीएस, माइक्रो एटाएम, ईएमओ जैसे और बहुत से ऐसे अन्य एप्लिकेशन के माध्यम से देश के अंतिम छोर तक नागरिकों को डिजिटल रूप से, वृद्धावस्था पशन, मनोरंगा आदि जैसी नागरिकों को लाभ का योजनाएं और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके इस उद्देश्य का समर्थन करती है।

प्रश्न 8. क्या ?

उत्तर : भावी सेवाएं :-

		स्थिति
1.	मेल प्रचालन, स्पीड पोस्ट बुकिंग और वितरण, पंजीकृत वस्तु बुकिंग और	क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है।
2.	आधार समर्थित भुगतान, जमा, अंतरण और बिल भुगतान	अग्रिम चरण में है और शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएंगी
3.	माइक्रो एटाएम, जमा, अंतरण और बिल भुगतान जैसे डाक विभाग काड आधारित भुगतान	शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।
4.	डाक जीवन बीमा - नई नीति और नवीकरण	परीक्षण के अंतिम चरण पर।
5.	पोस्ट बक एप्लिकेशन	विकास के अग्रिम स्तर पर
6.	बिक्री प्वाइंट - डाक-टिकट और अन्य डाक वस्तुएं	परीक्षण के अंतिम चरण पर और शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।

प्रश्न 9. क्या ? नयन के दौरान आने वाली चुनौतियां क्या हैं और इसका उपलब्धियां क्या ?

उत्तर : लक्ष्य प्राप्त करने में विभिन्न चुनौतियां थीं किन्तु सरकारों कमचारियों, उद्योग के विशेषज्ञों, परामशदाताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं का समर्पित टीम के कड़े परिश्रम से इन चुनौतियों पर काबू पा लिया गया है और निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं :

क्र.	1	2
1.	कनेक्टिविटी	मुख्य चुनौतियां देश के ग्रामीण भाग में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना थी जिसे निजी मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराया गया। लगभग 80 प्रतिशत रोलआउट स्थानों में सफलतापूर्वक लेन-देन हो रहा है

		अब तक 17 बिलियन से अधिक लेन-देन हुए हैं और इसका मूल्य 20 बिलियन ₹ है। प्रति लेन-देन कार्य का औसत मूल्य 1189 ₹ है।
2.	प्रशिक्षण	विभाग के अपने कमचारा प्रशिक्षक हैं ऑनलाइन प्रशिक्षण -अप किसी भी समय उपलब्ध है। 1 ₹ नवीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
3.	₹	जानकारी बढ़ाने के लिए 11 ₹ है। प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाने के लिए प्र प्रशिक्षण कक्षाएं तथा प्रबोधन कार्यक्रमों का 1 ₹ क्र 1 ज
4.	विद्युत की स्थिति	मण ग्रामीण भारत में विद्युत समान रूप से उपलब्ध है। 1 ₹ है 75% 1 व प्र 1 अलग से चाजिंग मॉड्यूल के साथ अतिरिक्त 1 प्रदान की गई है। 2 बैटरियाँ के साथ 3 1 1 1
5.	गांवों के लिए स्पी ₹	₹ ₹ तथा पंजीकृत डाक अब निकट स्थानों पर 1 आरआईसीटी उपकरणों ( 1 ₹ ) 1 ट्रैकिंग को भी सुविधा प्रदान की जा सकती है। रोयल टाइम ट्रैकिंग सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध लॉजिस्टिक कंपनियाँ ने भारतीय डाक के नेटवर्क का सुविधा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है ₹ 1 दि 1

१ प्र  
न १ १ - 110001

No. 12-10/2017-PMU (Pt) १ 20.12.2017